

ग्रामीण भारत के सर्वांगीण विकास में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों का योगदान एवं तुलनात्मक अध्ययन

Name- Rahul Verma

Post-Assistant Professor

Department-EAFM.

Office- Govt. PG College Pratapgarh Rajasthan

Mail id- Kathumriya.85@gmail.com

प्रस्तावना (Introduction)

भारत की लगभग 65-70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। महात्मा गांधी के अनुसार, "भारत की आत्मा गांवों में बसती है।" अतः राष्ट्र का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त न हो। बैंकिंग क्षेत्र इस सशक्तिकरण की रीढ़ है। 1969 के बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद से ग्रामीण बैंकिंग में आमूलचूल परिवर्तन आए हैं, जहाँ बैंकिंग का उद्देश्य 'व्यावसायिक बैंकिंग' से बदलकर 'सामाजिक बैंकिंग' हो गया है।

शोध के उद्देश्य (Objectives of Study)

ग्रामीण विकास में सार्वजनिक (PSBs) और निजी बैंकों (Private Banks) के योगदान का मूल्यांकन करना।

कृषि और सूक्ष्म उद्योगों (MSME) को दिए जाने वाले ऋण की प्रकृति को समझना।

दोनों क्षेत्रों के बैंकों के बीच तकनीकी और सेवा-स्तर के अंतर का विश्लेषण करना।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की विस्तृत भूमिका (Detailed Role of PSBs)

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (जैसे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि) सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन का प्राथमिक साधन हैं।

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion): 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' (PMJDY) के तहत खोले गए करोड़ों खातों में से अधिकांश सार्वजनिक बैंकों द्वारा खोले गए हैं, जिससे अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया।

रियायती ऋण (Subsidized Credit): किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से किसानों को बहुत कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, ताकि वे साहूकारों के शोषण से बच सकें।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT): गैस सब्सिडी, पेंशन और मनरेगा की मजदूरी सीधे बैंक खातों में भेजकर भ्रष्टाचार को कम करने में इन बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) का प्रायोजन: सार्वजनिक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करते हैं, जो विशेष रूप से केवल ग्रामीण बैंकिंग के लिए समर्पित होते हैं।

निजी क्षेत्र के बैंकों का बढ़ता प्रभाव (Growing Impact of Private Banks)

प्रारंभ में निजी बैंक केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित थे, लेकिन अब वे ग्रामीण बाजारों में "प्रॉफिट विद परपस" (लाभ के साथ उद्देश्य) के मॉडल पर काम कर रहे हैं।

कृषि मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण (Value Chain Financing): निजी बैंक केवल फसल उत्पादन के लिए ही नहीं, बल्कि कटाई के बाद के प्रबंधन, कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स के लिए भी ऋण प्रदान कर रहे हैं।

तकनीकी क्रांति: 'बायोमेट्रिक एटीएम', 'मोबाइल वैन बैंकिंग' और 'एआई-आधारित ऋण मूल्यांकन' के माध्यम से निजी बैंकों ने ग्रामीण ऋण वितरण को तेज किया है।

स्वयं सहायता समूहों (SHG) के साथ साझेदारी: आईसीआईसीआई और एक्सिस जैसे बैंकों ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए माइक्रो-लेंडिंग मॉडल को अपनाया है।

तुलनात्मक विश्लेषण तालिका (Comparative Analysis)

आधार (Parameter)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs)	निजी क्षेत्र के बैंक (Private Banks)
मुख्य उद्देश्य	सामाजिक कल्याण और वित्तीय समावेशन लाभ (Social Welfare)।	अर्जन और कार्यकुशलता (Profitability & Efficiency)।
पहुंच (Reach)	दूरदराज के गांवों और दुर्गम क्षेत्रों में व्यापक नेटवर्क।	मुख्य रूप से विकसित ग्रामीण केंद्रों और कस्बों तक सीमित।
प्रौद्योगिकी (Tech)	तकनीक अपना रहे हैं, लेकिन प्रक्रियाएं अक्सर पारंपरिक और समय लेने वाली होती हैं।	उन्नत तकनीक (AI, डेटा एनालिटिक्स) के कारण ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र।
वित्तीय समावेशन	जन धन योजना और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में अग्रणी (90% से अधिक योगदान)।	केवल उन क्षेत्रों में सक्रिय जहाँ व्यावसायिक संभावना अधिक है।
ग्राहक सेवा	ग्राहकों की भारी संख्या के कारण सेवा की गति व्यक्तिगत बैंकिंग और बेहतर ग्राहक अनुभव पर धीमी हो सकती है।	विशेष ध्यान।
ऋण की प्रकृति	छोटे और सीमांत किसानों के लिए रियायती ऋण (KCC) पर ध्यान।	एग्री-बिजनेस, कोल्ड स्टोरेज और ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के लिए बड़े ऋण पर ध्यान।

चुनौतियां (Challenges)

ग्रामीण बैंकिंग के मार्ग में कुछ प्रमुख बाधाएं अभी भी बनी हुई हैं:

एनपीए (NPA) की समस्या: कृषि ऋण माफी की उम्मीद और फसल की विफलता के कारण सार्वजनिक बैंकों में गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) का बढ़ना।

डिजिटल साक्षरता: ग्रामीण जनसंख्या में डिजिटल बैंकिंग के प्रति जागरूकता और विश्वास की कमी।

उच्च परिचालन लागत: ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने और उन्हें चलाने की लागत अधिक होती है, जो निजी बैंकों के लिए एक बड़ी चुनौती है।

सुझाव (Suggestions)

सहयोग मॉडल: सार्वजनिक बैंकों की 'विस्तृत पहुंच' और निजी बैंकों की 'तकनीकी दक्षता' को मिलाकर '**को-लेंडिंग (Co-lending)**' मॉडल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

वित्तीय साक्षरता: बैंकों को केवल ऋण देने तक सीमित न रहकर ग्रामीणों को वित्तीय नियोजन के बारे में शिक्षित करने के लिए शिविर लगाने चाहिए।

फिनटेक की भूमिका: मोबाइल बैंकिंग और बैंकिंग संवाददाताओं (Business Correspondents) का नेटवर्क और मजबूत किया जाए।

निष्कर्ष (Conclusion)

निष्कर्षतः, ग्रामीण भारत के सर्वांगीण विकास के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंकों की भूमिका पूरक (Complementary) है। जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 'सामाजिक न्याय' और 'सरकारी योजनाओं' के वाहक हैं, वहीं निजी क्षेत्र के बैंक अपनी 'नवीनता' और 'कुशलता' से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आधुनिकता ला रहे हैं। एक विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इन दोनों क्षेत्रों का समन्वित प्रयास अनिवार्य है ताकि ग्रामीण भारत केवल कृषि तक सीमित न रहकर एक सुदृढ़ आर्थिक केंद्र के रूप में उभरे।

संदर्भ (References):

1. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की वार्षिक रिपोर्ट।
2. नाबार्ड (NABARD) - ग्रामीण विकास सांख्यिकी।
3. आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) - भारत सरकार।

विस्तृत संदर्भ सूची (Extended Bibliography)

सरकारी रिपोर्ट और प्रकाशन (Government Reports & Publications):

- **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI):** "रिपोर्ट ऑन ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया" (विभिन्न वर्ष)। यह ग्रामीण ऋण के आंकड़ों के लिए सबसे विश्वसनीय स्रोत है।
- **नाबार्ड (NABARD):** "वार्षिक रिपोर्ट" और "स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स ऑफ आर.आर.बी." (Regional Rural Banks)।
- **भारत सरकार (वित्त मंत्रालय):** "आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) 2023-24 और 2024-25"।
- **मंत्रालय (MoSPI):** राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी ग्रामीण विकास संबंधी सर्वेक्षण।

पुस्तकों के संदर्भ (Books):

- **देसाई, एस. एस. एम.:** "रूरल बैंकिंग इन इंडिया" (Rural Banking in India), हिमालय पब्लिशिंग हाउस।
- **रेड्डी, के. वेंकट:** "एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट", वीएचपी पब्लिकेशन।
- **भार्गव, बी. के.:** "इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम", मैकमिलन पब्लिशर्स।

जर्नल और शोध पत्र (Journals & Research Papers):

- **EPW (Economic and Political Weekly):** ग्रामीण ऋण और वित्तीय समावेशन पर विशेष लेख।
- **Journal of Rural Development:** राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (NIRD) द्वारा प्रकाशित शोध पत्र।